

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes, Sir.

(b) Steps have been taken to improve the Railway track of Naupada-Gunupur line on a programmed basis. A traffic survey for the conversion of the Rupsa-Talband section into Broad Gauge has been carried out and the report is under the examination by the Railway Board.

Import of Tea from India by Iraq

*755. SHRI RAJDEO SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Indian Tea is becoming more popular in Iraqi market;

(b) whether in the recently concluded Indo-Iraqi trade agreement, it is provided that Iraq will import 20 per cent of her total tea requirements from India ; and

(c) if so, the quantity of tea likely to be purchased by Iraq from India in 1972 ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Yes, Sir.

(b) There is no stipulation in the Indo-Iraq trade agreement that Iraq will import 20 per cent of her total tea requirements from India. The agreement *inter alia* provides for purchase of tea worth 2.6 million sterling £ by Iraq during the agreement period from 1-9-1971 to 31-3-1973.

(c) Worth about Rs. 2 crores.

Survey of Arabian Sea for Development of Fishing Under AID from U. N. F. & A. O.

5215. SHRI VAYALAR RAVI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to conduct an Oceanic Survey in the Arabian Sea with Norwegian Cooperation for the development of fishing under the aid programme of United Nations Food and Agricultural Organisation;

(b) if so, the main features of the scheme; and

(c) the time by which this survey is expected to start ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHAB P. SHINDE) : (a) to (c). A Project for the investigation of the pelagic fishery resources of the South West Coast has already been taken up with assistance from the United Nations Development Programme. The Norwegian Agency for International Development is associated with the project as sub-contractors to the United Nations Development Project. The scheme has become operational with effect from February 1971 and is to continue for a period of 5 years. Under this programme two vessels equipped with modern acoustic devices for location of fish are being provided by the International Agency. One of the vessels had been received and has commenced survey operations. The other vessel is expected to be received in the course of the year. The object of the Investigation is to locate overall resources of Sardines and Mackerel.

मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का दूर किया जाना

5216. श्री मारतण्ड सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के रोवा डिबीजन के विभिन्न जिलों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन-कौन-से कार्य आरम्भ किये गये और उससे 1970-71 में कितने लोगों को रोजगार मिला, और

(ख) इस बारे में जिला-वार कितनी प्रगति हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० गौर सिंह) : (क) और (ख). ग्राम रोजगार की त्वरित योजना वर्ष 1971-72 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के

अन्तर्गत मध्य प्रदेश के रोवा डिबीजन के विभिन्न जिलों में जो निर्माण कार्य आरम्भ किये गये हैं, उनमें सड़कें तथा सधु सिंचाई कार्य शामिल हैं। वृत्त लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या तथा उनकी रोजगार की अवधि प्रत्येक परियोजना की भिन्न-भिन्न है, अतः इस योजना के अन्तर्गत रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या की अपेक्षा पैदा किये गये रोजगार के श्रमदिनों की संख्या देना अधिक उपयुक्त है। उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1971-72 में रोवा डिबीजन के विभिन्न जिलों में पैदा किये गये रोजगार के श्रमदिनों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1971-72 में मध्य प्रदेश के रोवा डिबीजन के विभिन्न जिलों में आरम्भ किये गये निर्माण कार्यों का स्वरूप, किया गया व्यय तथा पैदा किया गया रोजगार दर्शाने वाला विवरण।

जिला	निर्माण कार्य	किस अवधि तक की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।	किया गया व्यय (हजार रु० में)	पैदा किये गये रोजगार के श्रम दिन (हजार श्रम-दिनों में)
1	2	3	4	5
1. टीकमगढ़	सड़कें	फरवरी, 72	26.27	2.53
2. खैरपुर	सधु सिंचाई	"	4.21	0.55
3. पन्ना	सधु सिंचाई तथा सड़कें	"	50.68	26.44
4. सदाशिवपुर	सधु सिंचाई तथा सड़कें	"	2.94	1.18
5. रोवा	सधु सिंचाई तथा सड़कें	"	12.13	4.84
6. झांझार	सधु सिंचाई तथा सड़कें	"	0.70	1.45
7. सिधौ	सधु सिंचाई तथा सड़कें	"	69.26	41.26
			166.19	78.25

Profit to a Farmer on Sale of Wheat

5217 SHRI RANABHADUR SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the net profit to an average small farmer on sale per quintal of wheat at the newly proposed prices of the Agricultural Prices Commission ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) The Agricultural Prices Commission recommended that the procurement prices for wheat for 1972-73 season (corresponding to 1971-72 crop season) be fixed uniformly for all the States at Rs 66 per quintal for the indigenous red and Rs 72 per quintal for the indigenous common white and the different Mexican varieties. The Government have, however, decided to retain the procurement prices at the previous year's level, i.e. at Rs 71.74 per quintal for indigenous red variety and Rs 76 per quintal for other varieties.

For estimating the net profit to an average small farmer on sale per quintal of wheat at the newly proposed prices, data cost of production of wheat in respect of an average small farmer is required for the corresponding crop season, i.e. 1971-72. Such data for 1971-72 crop season are not available.

Study of Cost of Production of one Quintal of Wheat by a Farmer

5218 SHRI RANABHADUR SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state .

(a) the cost of production of one quintal of wheat by a small farmer who uses no machinery;

(b) whether any study has been made in this regard,

(c) the break-up of such a calculation, and

(d) the rate at which the prices of the inputs have been calculated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) (a) to (d). No All-India survey has been carried out to assess specifically the cost of production of one quintal of wheat by a small farmer who has used no machinery.

1968-69, 1969-70 और 1970-71 में मध्य प्रदेश में कपास, चावल, गेहूँ तथा ज्वार का उत्पादन

5219. श्री गंगा चरण दीक्षित क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1970-71 में कपास, चावल, गेहूँ तथा ज्वार का कितना उत्पादन हुआ है,

(ख) क्या वर्ष 1968-69 और 1969-70 की तुलना में 1970-71 में उक्त वस्तुओं का उत्पादन अधिक था; और

(ग) उक्त राज्यों में इन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी. शिन्डे) : (क) वर्ष 1970-71 की अवधि में मध्य प्रदेश में इन जिलों के उत्पादन की मात्रा निम्न प्रकार की :—

1. कपास 2.14 लाख गांठे (प्रत्येक 180 किलोग्राम की)
2. चावल 36.47 लाख मीटरी टन
3. गेहूँ 25.28 लाख मीटरी टन
4. ज्वार 14.07 लाख मीटरी टन

(ख) वर्ष 1970-71 की अवधि में चावल तथा गेहूँ का उत्पादन 1968-69 तथा 1969-70 के उत्पादन की तुलना में अधिक था और कपास तथा ज्वार का उत्पादन कम था।

(ग) चावल, गेहूँ तथा ज्वार के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से, राज्य में अधिक उत्पादनशील किस्मों का क्षेत्र बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं। इसके प्रतिरिक्त, वनस्पति रक्षण कार्यों को तीव्र किया जा रहा है और कृषक प्रशिक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जा रहा है। कपास का उत्पादन केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित अर्थात् अधिकतम कपास उत्पादन तथा सघन कपास जिला कार्यक्रम द्वारा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त आगामी दो वर्षों की अवधि में कपास के सकर-4 बीजों के उत्पादन को एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेज के लिये चिकित्सा की एकीकृत प्रणाली

5220. श्री गंगा चरण दीक्षित क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा की एकीकृत प्रणाली मध्य प्रदेश में भी प्रारम्भ कर दी गई है और क्या सरकार ने उक्त प्रणाली के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, और

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य सची (प्र० डी० पी० जेट्टी-

पाठ्याय) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

शिक्षा प्रयोजनों के लिये गुजरात और उड़ीसा को अनुदान

5221. श्री गंगा चरण दीक्षित क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में गुजरात तथा उड़ीसा की शिक्षित योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान लिये कितना अनुदान दिया गया

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) अर्थात् सूचना एकत्र की जाती है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समाज कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं के पुनरीक्षण वेतनमानों के लिये अनुदान

5222. श्री गंगा चरण दीक्षित क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रों यह बताने का कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान समाज कल्याण विभाग के सामाजिक कार्यकर्ताओं के वेतनमानों और महंगाई भत्तों के नियतन तथा पुनरीक्षण के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण निधि में से मध्य प्रदेश का अनुदान आवंटित किये गये थे और

(ख) यदि हा, तो उक्त कार्यकर्ताओं के वेतनमान और महंगाई भत्ता क्या है और मध्य प्रदेश का वर्ष-वार कितना अनुदान दिया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण
मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस्०
रामास्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Unemployment due to Green Revolution
and Mechanisation of Agriculture

5223. SHRI MARTAND SINGH :
Will the Minister of AGRICULTURE be
pleased to state :

(a) whether there has been an increase
in unemployment due to the Green Revolu-
tion and mechanisation of Agriculture;
and

(b) if so, the steps Government have
taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI
ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) No,
Sir. The term "Green Revolution" is
generally being used for the success of
New Strategy of Agriculture Develop-
ment adopted since 1966-67. The implemen-
tation of this New Agricultural Strategy
consisting of High Yielding Varieties and
Multiple Cropping Programmes has
increased the intensity of farming and thus
created more employment opportunities in-

spite of the partial mechanisation of
Agriculture.

(b) Does not arise.

Central Grants to States for Integrated
Dry Land Agricultural Development

5224. SHRI MARTAND SINGH :
SHRI RANABAHADUR SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE
be pleased to state :

(a) the amount of loans and grants
provided to the States according to the
Scheme, for the Integrated Dry Land
Agricultural Development during the last
two years, State-wise;

(b) whether any of the States have
approached for more loans and grants to
the Union Government; and

(c) if so, the main features thereof and
action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI
ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) An
amount of Rs 190 66 lakhs was provision-
ally released to the State Governments
for the Integrated Dry Land Agricultural
Development Scheme during the last two
years, subject to adjustments on the
basis of the audited figures of expenditure.
State-wise break-up is given below :

(Rs. in lakhs)

S. No.	State	1970-71			1971-72		
		Loan	Grant	Total	Loan	Grant	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Andhra Pradesh	0.35	1.80	2.15	12.02	8.93	20.95
2.	Bihar	—	—	—	0.50	2.85	3.35
3.	Gujarat	—	1.35	1.35	2.00	5.80	7.80
4.	Haryana	12.54	8.31	20.85	14.15	4.42	18.57
5.	Jammu & Kashmir	—	—	—	0.23	0.50	0.73

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Maharashtra	—	0.91	0.91	6.65	7.57	14.22
7.	Madhya Pradesh	1.28	1.07	2.35	1.70	7.89	9.59
8.	Mysore	—	1.67	1.67	4.35	2.83	7.18
9.	Orrisa	—	—	—	0.50	1.30	1.80
10.	Rajasthan	7.71	2.78	10.49	10.13	6.42	16.55
11.	Tamil Nadu	0.40	1.14	1.54	2.20	10.14	12.34
12.	Uttar Pradesh	1.60	1.97	3.57	16.35	16.35	32.70
	Total	23.88	21.00	44.88	70.78	75.00	145.78

(b) and (c). Yes, Sir Additional loans/grants requested by State Governments are given below :—

(Rs. in lakhs)				
S. No.	State	Loan	Grant	Total
1.	Andhra Pradesh	0.01	3.05	3.06
2.	Bihar	—	1.17	1.17
3.	Gujarat	—	1.78	1.78
4.	Haryana	0.04	1.83	1.87
5.	Madhya Pradesh	0.04	2.83	2.87
6.	Maharashtra	0.03	2.52	2.55
7.	Mysore	0.08	0.90	0.93
8.	Rajasthan	0.02	1.84	1.86
9.	Tamil Nadu	—	3.42	3.42
10.	Uttar Pradesh	0.05	6.01	6.06
11.	Jammu & Kashmir	0.77	2.17	2.94
	Total :—	0.99	27.52	28.51

These additional requirements could not be accommodated within the estimates of expenditure for 1971-72. When the State Governments will submit the actual expenditure in accordance with the administrative approval of the Government of India, the said amount would be enhanced for release.

Suction Curettage

5225. SHRI VAYALAR RAVI. Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have received any report regarding the adoption of an easy technique for abortion, called 'Suction Curettage' in our country in the light of the present liberalisation of Abortion law, and

(b) if so, the gist thereof and the reaction there to ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) and (b) The Vacuum Aspirator for doing termination of pregnancy by 'Suction Curettage' is being used in some centres in the country. The report of their use is still awaited.

Foreign Students in India

5226. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state

(a) the number of foreign students in India; and

(b) the number out of them who are studying with Indian scholarships and the names of private institutions, if any, giving scholarships to foreign students to study in India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : (a) According to the available statistical data which relates to the year 1969-70, the total number of foreign students studying in India is 2,549.

(b) Scholarships are given to foreign students for studying in India by the

Ministry of Education and Social Welfare under the Schemes of General Cultural Scholarships, Cultural Exchange Programmes, Colombo Plan, Special Commonwealth African Assistance plan and Commonwealth Scholarships and Fellowships. The total number of students who are in receipt of these scholarships for studying in India during 1971-72, is 997. The Indian Council for Cultural Relations also offers six scholarships every year to foreign students for study of Indian History, Philosophy and other aspects of Indian Culture. Information regarding scholarships given to foreign students by private institutions for study in India is not available.

लहाख, कश्मीर में फलों का उत्पादन

5227. श्री कुशोक बाबूला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने लहाख में फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है जिनमें वहाँ पर 'जाम' उद्योग को विकसित किया जा सके तथा उनकी बिक्री से उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Annual General Body meetings of Kohata Cooperative House Building Society

5228. SHRI SARJOO PANDEY : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the dates on which the Annual General Body meetings of the Kohat Coop-

erative House Building Society have been held since its inception;

(b) whether the annual meetings of the Society are not being held regularly, and

(c) if so, the steps taken by the Registrar, Cooperative Societies to ensure holding of regular meetings of the Society ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL): (a) The meetings were held on following dates:—

1. 12-6-1949.
2. 21-1-1964
3. 9-2-1964.
4. 23-2-1964
5. 16-8-1964.
6. 21-2-1965.
7. 21-3-1965.
8. 7-11 1965.
9. 9-4-1967
10. 21-4-1968
11. 4-10-1970.

(a) and (c) Through various audit and inspection notes, the Society was directed to hold General Body meetings regularly. On 19th February, 1970, a General Body meeting was requisitioned by the Registrar which resulted in the meeting held on 4th October, 1970. The Society has again been directed to hold General Body meetings annually in accordance with the provisions of law and bye-laws of Society.

Kohat Cooperative House Building Society

5229. SHRI SARJOO PANDEY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether the Kohat Cooperative House Building Society has submitted its lay out plan and if so, when the plan was submitted and where the matters stand at present,

(b) by what time the plan is likely to be approved, and

(c) the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL): (a) and (b). Yes Sir A revised Layout Plan submitted on 2nd May 1972 is under examination of Delhi Development Authority. If it is found to be in order, it will be placed before the next meeting of the Authority

(c) The earlier Layout Plan submitted by the Society was not in accordance with the provision of Master Plan/General Development Plan

Auditing of Accounts of the Kohat Co-operative House Building Society

5230 SHRI SARJOO PANDEY Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state

(a) whether the accounts of the Kohat Co-operative House Building Society have been audited on behalf of the Registrar Co-operative Societies regularly and if so, at what intervals this was done and on what dates .

(b) in case no auditing has been done on behalf of the Registrar, the reasons therefor .

(c) whether the accounts of the Society have been checked by authorised auditors other than Government auditors and if so, the years for which this has been done since inception .

(d) if the action as in part (c) has been taken, the manner in which the Registrar,

Co-operative Societies ensures that the deposits of the Members of the Societies are not misused by the office-bearers etc. of the Societies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes, Sir. The years and dates of the audit are as under :—

Accounts for the cooperative year (1st July to 30th June) audited.	Date on which the audit completed.
--	------------------------------------

1954-55	9-3-1956
---------	----------

1958-59	23-9-1960
---------	-----------

1959-60	
---------	--

1961-62	7-6-1963
---------	----------

1962-63	2-7-1963
---------	----------

1963-64	4-1-1965
---------	----------

1964-65	9-2-1970
---------	----------

1965-66	27-5-1970
---------	-----------

1966-67	28-6-1971
---------	-----------

1967-68	5-7-1971
---------	----------

1968-69	
---------	--

1969-70	5-8-1971
---------	----------

1970-71	
---------	--

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Since the accounts have been audited on behalf of the Registrar, the question does not arise.

Promotion and Confirmation of Class III and IV Employees of Sahitya Akademi

5231. SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the methods of promotion and confirmation of class III and IV employees working in Sahitya Akademi, New Delhi ; and

(b) the number of Class III and IV employees who have put in more than eight years of service in their respective grades ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE : (SHRI D. P. YADAV) (a) Promotion and confirmation of all employees working in the Sahitya Akademi are governed by the provisions of its service bye-laws, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) 8 in Class III ; and

16 in Class IV.

Rent For Retention of Quarters by Officials of Sahitya Akademi

5232. SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the amount being paid on payment of market rents for retention of two quarters by two officials of the Sahitya Akademi, New Delhi ; and

(b) the monthly expenditure on this score and total amount spent by the Akademi so far on this account ?

THE DEPUTY MINISTER FOR EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : (a) The two officials of the Sahitya Akademi who are occupying Government accommodation are not drawing any house rent allowance. The difference between the rents paid by the officers under FR 45A and the market rate is being met by the Sahitya Akademi. At present this amount is Rs. 950 per month approximately.

(b) The amount paid by the Sahitya Akademi on the above score is about

Rs. 950 per month. The amount thus spent by the Akademi during the last 7 years is about Rs. 25,000 after taking into account the usual admissible House Rent Allowance that would have been paid to the two officers if no Government accommodation had been given to them.

Provision of Government Accommodation to Low Paid Staff of Sahitya Academy

5233. SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government accommodation are not provided to low paid staff of the Sahitya Academy, New Delhi ; and

(d) if so, whether Government propose to extend this facility in future to them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : (a) No, Sir.

(b) Owing to acute shortage of Government residential accommodation in Delhi, it has not been possible to make the employees of the Sahitya Akademi eligible for Government accommodation in the general pool.

Implementation of Recommendations made by Programme Expert Committee on Sahitya Akademi

5234. SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether Sahitya Akademi is unable to implement its programme Expert Committee's recommendations to fill up certain lower posts for want of funds ;

(b) if so, the number of posts, category-wise, not filled up for want of funds during last three years ; and

(c) whether the post of Regional Secretary, Bombay, has been advertised instead of extending the economy to this post also ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : (a) No programme Expert Committee has been appointed by the Akademi. As such the question of not implementing the recommendations of the programme Expert Committee to fill up the posts by the Akademi does not arise.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir. The post of Regional Office Secretary, Bombay has been advertised. This is not a new post. The post which belongs to the Head Office of the Sahitya Akademi and has been vacated by the elevation of the senior-most Assistant Secretary as Secretary, has been transferred to the Regional Office of the Akademi set up recently at Bombay.

Recruitment to post of Superintendent in Sahitya Akademi, New Delhi

5235. SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the method followed for recruitment to the grade of Superintendent in Sahitya Akademi, New Delhi ; and

(b) whether it is being strictly followed for filling up all the posts of Superintendents ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) The recruitment to the post of Superintendent in the Sahitya Akademi is governed by the provisions of its service bye-laws, copies of which are available in the Parliament library.

(b) Yes, Sir. There is, however, one post of Superintendent in the Sahitya Akademi.

**Assistance for Housing Scheme in
Andhra Pradesh**

5236. SHRI Y. ESWARA REDDY : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government are in receipt of any request made by Andhra Pradesh Government for approval and financial assistance to the housing schemes decided to be taken up in thirty municipalities;

(b) if so, the names of the municipalities and broad outlines of the schemes, municipality-wise; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) to (c). The Government of Andhra Pradesh had requested for a grant of approximately Rs. 1.25 crores under the new Central Scheme for environmental improvement to take up improvement of slum areas in 30 municipalities. For the present only the city of Hyderabad is eligible for grant assistance under the new scheme. The Government of Andhra Pradesh have been informed accordingly. Project proposals for environmental improvement of 3 slum areas received from the Municipal

Corporation of Hyderabad have been approved on the total estimated cost of Rs. 38,42,100 and a sum of Rs. 9,63,000 has been released as first instalment.

**Construction of Houses under Various
Housing Schemes in Andhra Pradesh**

5237. SHRI V. ESWARA REDDY : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the number of houses built in Andhra Pradesh under the Subsidised Industrial Housing Scheme, Low Income Group Housing Scheme, Middle Income Group Housing Scheme, and the Rural Housing Scheme, separately District-wise; and

(b) the number of people benefited under each of the above schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) According to the progress reports received so far from the Government of Andhra Pradesh, the number of houses built in the State under each scheme is given below :—

<i>Name of Scheme</i>	<i>No. of houses built</i>
1. Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Section of Community ...	5,846
2. Low Income Group Housing Scheme ...	9,690
3. Middle Income Group Housing Scheme ...	2,225
4. Village Housing Projects Scheme ...	4,220
TOTAL :	21,981

District-wise figures are not maintained in the Ministry.

(b) The number of families benefited under each scheme would be equal to the number of houses built thereunder. The number of persons benefited would, therefore, be approximately five times the number of families.

Scholarships to Handicapped in Andhra Pradesh

5238. SHRI Y. ESWARA REDDY : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the number of applications for Scholarships from handicapped persons and the number of Scholarships granted in 1971-72 and 1972-73 in Andhra Pradesh, year-wise, districtwise and separately for boys and girls ;

(b) the number of applications for lumpsum discretionary grants for the handicapped persons and the number of persons given such grants in Andhra Pradesh for the same period, year-wise and district-wise; and

(c) the requisite qualifications for the scholarships and its continuance ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. S. RAMASWAMY): (a) The position is as under :

Year	Number of applications received from physically handicapped students	Number of scholarships awarded
1971-72	165	88 (76 boys and 12 girls)

1972-73 Applications for the year have yet to be received. The last date for receipt of applications during this year is 31st August, 1972.

District-wise figures are not available.

(b)

Year	Number of applications received from handicapped persons for discretionary grant	Number of persons given grant
1971-72	3 (2 from Hyderabad District; 1 from Guntur District)	1 (from Hyderabad District).
1972-73	No application has been received so far in the year 1972-73 which has just commenced.	

(c) A copy of the rules regulating award of scholarship to the physically handicapped which furnishes detailed information regarding eligibility requirements is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1971-72]

Removal of Unauthorised Tea Stalls in D. I. Z Area

5239. SHRI M. S. SIVASWAMY : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether one unauthorised tea stall which came into existence at the time of the construction of Types II and III quarters in D.I.Z. Area, New Delhi is still running in the locality;

(b) whether any steps have been taken to remove that unauthorised construction which has become a nuisance,

(c) the times by which it is likely to be removed, and

(d) the steps taken in the matter and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). Action to remove the tea stall was initiated after the completion of the building work of Type II quarters. The contractor, who is now engaged in the execution of works relating to roads and storm water drains, however, still needs the tea stall for use by his labourers and has taken the responsibility for removal of the said tea stall as soon as the road work is completed. The road work is nearing completion and it is expected that this tea stall will be removed shortly. Completion certificate for the works will not be issued to the contractor unless he removes this tea stall.

Collection of Funds for Construction of Cancer Hospital in Delhi

5240. **SHRI DEVINDER SINGH GARCHA :** Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to a press report (*Times of India* Delhi, dated 26th April, 1972) that Rotary Club of Delhi has decided to raise funds for the construction of a cancer hospital in Delhi at the cost of 50 lakh of rupees which will cater to the needs of Northern States ;

(b) if so, whether Government has contributed anything for the proposed hospital; and

(c) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) to (c). The Rotary district 310, comprising the Rotary Clubs in Punjab, Haryana Delhi and U. P. have

established a Cancer Foundation in Delhi which has a proposal to set up a big Cancer Project consisting of a large hospital with 300 beds and out-patient wing, as also research laboratory and a training institute for work of cancer. The project is estimated to cost about rupees two crores to begin with. Though it will not be possible for the Central Government to give any financial help for the establishment of Cancer Hospital, medical aid being State subject, the Central Govt., would give the Cancer Foundation all other necessary help and technical guidance. The Cancer Foundation has been requested to draw up a complete scheme giving full details of expenditure of the proposed hospital. The Foundation has not yet sent the detailed scheme.

Steps to reduce margin between Procurement and sale price of Rice

5241. **SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA :** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether a very big margin exists between the procurement and the sale prices of rice through the fair price shops and if so, the main features thereof;

(b) how much of this amount (the margin between procurement and sale price) is being utilised by middlemen, Government distribution machinery and the commissions given to fair price shops; and

(c) the steps being taken to bring about economy in this regard so that the big margin between the procurement and sale price of rice is reduced and it is made available to consumers at a cheaper rate ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Rise in Price of Commodities sold at Super Bazar, Delhi

5242 SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the *Hindustan Times* Evening News dated 26th April, 1972 that the prices of some of the commodities in Super Bazar have risen recently,

(b) if so, the commodities where the rise in price has become significant, and

(c) whether the increase in the price has been due to the fact that the saleable commodities in Super Bazar, where the prices have risen, are being purchased through a contractor and if so, the factors responsible for the rise in prices and the steps Government propose to take to curb it ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAGANNATH PAHADIA) (a) Yes, Sir

(b) and (c) The news item refers to prices of vegetables and fruits in the Super Bazar, New Delhi. The authorities of the Super Bazar have carried out a market survey, which shows that there was no significant difference between the prices of fruits and vegetables in the Super Bazar and those obtaining in comparable markets of Delhi. However, there was some difference in price in respect of a few items as compared with the rates in the Pabargunj Market. This was immediately taken note of and prices of those items revised accordingly. The Fruits and Vegetables Section in the Super Bazar is being run under special arrangements with a private party, but, in accordance with the terms of agreement, the Super Bazar exercises check on the quality and price, for which comparison is also made with the market. In view of the

check exercised by the Super Bazar, normally there is no likelihood of the prices of comparable qualities of fruits and vegetables, or of other goods sold under similar arrangements in the Super Bazar, being higher than the market prices

India as Second Largest Rice Producing Country

5243 SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state

(a) whether India has attained the position of being the second largest rice producing country in the world,

(b) whether it makes the country self sufficient and also provides any surplus, and

(c) if so, the surplus that has been achieved and whether the issue price of rice through the ration/fair price shops will be reduced in view of the above position ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P SHINDE) (a) India has been the second largest rice producing country in the world for the last several years

(b) The production of rice is adequate to meet the requirements at the current level of consumption without any imports

(c) Does not arise

Procurement Price, Sale Price and Subsidy on Sale of Foodgrain's Consumed by Poor People

5244 SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the foodgrains that are being procured by Government or through Central Government's agency ;

(b) the procurement price and sale price of each commodity ; and

(c) the foodgrains in respect of which Government are giving any subsidy and the amount thereof and whether Government have under consideration any plan for selling those food items, which are consumed by poorer section of the community, at a cheaper rate even with some subsidy, if necessary, and if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P SHINDE) :

(a) Wheat and rice are being procured on behalf of Government by the Food Corporation of India.

(b) Procurement price of wheat is Rs. 76 per quintal and issue price is Rs. 78 per quintal. Procurement price of rice varies from State to State. A statement showing Statewise prices is attached. Issue prices of rice are given below:-

Coarses	Rs. 100	per	quintal.
Medium	Rs. 111	"	"
Fine	Rs. 120	"	"
Superfine	Rs. 128	"	"

(c) At present, distribution of both wheat and rice is being subsidised. The subsidy paid in 1971-72 was Rs. 44.21 crores for wheat and Rs 5.48 crores for rice.

The Food Corporation is also procuring and selling coarse grains at reasonable prices which are mainly consumed by poorer section of society

Statement

Procurement prices of Standard variety of rice in the various States during 1971-72 season

			(Rs per quintal)
S. No.	Name of State	Standard variety	Procurement price for 1971-72
1.	Andhra Pradesh	Akullu	80.32
2.	Assam	Winter Salt	—
3.	Bihar	Coarse	95.25
4.	Gujarat	Sathi	85.34
5.	Haryana	Begmi	85.50
6.	Kerala	Palghat Matta	85.88
7.	Madhya Pradesh	Gurmatia	83.00
8.	Maharashtra	Coarse	81.00
9.	Mysore	Coarse (raw)	74.30
10.	Orissa	Medium	95.20
11.	Punjab	Begmi	85.50
12.	Rajasthan	Suthersaul	—
13.	Tamil Nadu	Kattaisamba	88.31 (Boiled)
14.	Uttar Pradesh	Grade IH	89.00
15.	West Bengal	Common	91.20

**Setting up of Regional units of
National Nutrition Monitoring Bureau**

5245. SHRI VAYALAR RAVI. will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to start regional units of National Nutrition Monitoring Bureau in different States :

(b) if so, the nature of works assigned to these units; and

(c) whether Government will set up such a unit in Kerala ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTO-PADHYAYA) : (a) Yes With effect from the 1st April, 1972, the Indian Council of Medical Research has started Regional National Nutrition Monitoring Bureau in the states of Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal

(b) The primary objective of the Units would be to collect information on the nutritional status and its determinants, among different segments of the population in the country and through repeating these studies once in a year, to provide information on the changes that have occurred as well as the reasons for such changes. The regional centres would also undertake clinical nutrition surveys, anthropometric measurements : family diet surveys, individual diet surveys; and collection of other relevant data like food production and food availability etc. One of the important functions of the National Nutrition Monitoring Bureau is the continuous evaluation of on-going nutritional programmes, the results of which could be fed-back with a view to providing such mid-course correction as may be needed in the operation of the nutritional programmes of the country.

(c) The Indian Council of Medical Research has already set up, with effect from the 1st April, 1972, one unit of the National Nutrition Monitoring Bureau in Kerala.

**International Crops Research Institute
For Semi-Arid Tropics**

5246. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA :
SHRI C. T. DHANDAPANI :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the time when which the unit of International Crops Research Institute for semi-arid tropics is expected to be completed;

(b) whether the unit is being set by indigenous material and money or with foreign collaboration; and

(c) if so, main features thereof and the amount of foreign exchange proposed to be spent on the unit ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHAB P. SHINDE) : (a) An Agreement has been concluded on 28-3-72 between the Government of India and the Ford Foundation acting on behalf of the Consultative Group on International Agricultural Research for the establishment of an International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics in India. The Institute is likely to come up during this year.

(b) The Institute is being set up by the Consultative Groups on International Agricultural Research. Financial support to the Institute will be given by the said Group which includes International Bank for Reconstruction and Development, United Nations Development Programme,

International Development Research Centre Governments of U. K., West Germany etc.

(c) A statement continuing the note outlining the main features of the Institute is enclosed. No foreign exchange expenditure on the part of the Govt. of India is involved.

STATEMENT

The Government of India have concluded a Memorandum of Agreement with the Ford Foundation acting on behalf of the Consultative Group on International Agricultural Research for the establishment of an International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics.

2. The Institute will be an autonomous, international, philanthropic non-profit, research, educational and training organisation.

3. The Institute will serve—as (a) a World Centre for the improvement of Jowar, Millets, red gram (arhar) and Bengal gram (chana); (b) a centre to promote the development and demonstration of improved cropping patterns and systems of farming which optimum the use of human and natural resources in the low rainfall, unirrigated, seasonally dry and semi arid tropics and (c) a centre undertaking research in similar fields.

4. An initial grant of \$ 4,00,000/- has been pledged by the International Bank for Reconstruction and Development, UNDP, USA and U. K. for the establishment of the Institute.

5. The Institute will supplement the national programme on Dryland Farming of the Government of India. It has immense potentialities of revolutionising agricultural production not only in non-irrigated areas of India but also in seasonally dry semi-arid tropical zones in the world by improved seeds, cropping patterns, farming practices and optimum

use of human and natural resources. It is estimated that nearly 400 million people in the world will stand to benefit from the Institute.

Financial Assistance to Andhra Pradesh for Drought Affected Areas

5247 SHRI. Y. ESWARA REDDY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the amount of total financial assistance so far given to Andhra Pradesh Government to solve the problems of chronically drought affected areas in the State during the last three years;

(b) the names of the schemes for which assistance has been given and how far these schemes have progressed;

(c) whether the State Government has demanded additional assistance for drought affected areas; and

(d) if so, what action has been taken thereon "

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) (a) The Drought Prone areas Programme was introduced in 1970-71 mainly with the objective of mitigating the severity of scarcity conditions in 54 selected chronically drought affected districts of the country. For the 5 districts of Andhra Pradesh, which are covered under the programme, a total outlay of Rs. 10 crores will be available over the period from 1970-71 to 1973-74. A total assistance of Rs. 525.79 lakhs was provided to the State Government during 1970-71 and 1971-72 for the schemes approved under the programme.

(b) The assistance was given for minor irrigation, soil conservation, afforestation, roads and drinking water supply schemes sanctioned under the programme. The

trend of expenditure on the sanctioned schemes indicated a satisfactory progress

(c) Yes, Sir.

(d) The Government of India have agreed to provide an additional outlay of Rs 64 lakhs to the State Government for extending the programme to two chronically drought affected talukas, namely, Devarkonda Taluk of Nalgonda District and Kanigiri Taluk of Prakasam (Ongole) District, which are contiguous to the already selected districts

Utilisation of Funds Allocated for Drought Affected Areas

5248. SHRI Y. ESWARA REDDY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state .

(a) whether the funds allotted for the scheme for chronically drought affected areas during the year 1970-71 and 1971-72 had not been used fully;

(b) if so, the amount of actual shortfall in expenditure for these two years,

(c) the reasons for the shortfall, and

(d) the steps Government have taken to ensure full utilisation of the funds allotted for the schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF SHER SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central budget provisions and the actual shortfalls are shown below .

	(Rs. in crores)	
	1970 71	1971-72
Budget provision	25 00	20 00
Shortfall	15 95	1.5

(c) During 1970 71, which was the first year of the Programme several preparatory steps had to be taken at Central and

State levels. Detailed data had to be collected from the States for identification of the chronically drought prone districts. Guidelines had to be prepared and circulated to the States for formulation of schemes under the programme. The States had taken time for preparation of the detailed project reports for the Programme districts. However, even during the first year of the Programme (1970-71) schemes had been sanctioned by the Centre in 45 of the 54 selected districts. Thereafter the States had to follow the usual, technical administrative and financial procedures for sanctioning the individual schemes and also build up the necessary organisation for their implementation. For these reasons, the budget provision could not be fully utilised. However, during 1971-72 the programme implementation has been stepped up and the entire grant portion of the budget was utilised. The loan portion (which is Rs 1 50 crores) could not be utilised because the State Governments did not furnish separately the figures of expenditure for which the Central assistance is in the shape of loan.

(d) The programme has now been sanctioned in all the 54 districts. Schemes with a total estimated cost of Rs 76 67 crores have been cleared and the State Govts have thus in hand a large programme for implementation. Instructions have been issued to the States to proceed with the interruption of the sanctioned schemes without implementation. Preliminary measures have been mostly completed and most States have built up the necessary organisation for speedier implementation of the Programme.

Centrally Sponsored Scheme in Orissa

5249. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether any scheme has been initiated in Orissa under the scheme of Special Investigation Divisions, where 100 per cent central assistance is given to the States;

(b) if so, the number of such schemes and the places in Orissa, where this has been initiated by now;

(c) the amount spent and result achieved so far in the Central and the Centrally sponsored sectors in Orissa, and

(d) whether the Orissa Government has prepared detailed plans and estimates for difficult and scarcity areas by now and if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF D P CHATTOPADHYAYA) (a) to (d) Under the Centrally Sponsored Scheme of Special Investigation Divisions, one Division with three Sub-divisions has been functioning in Orissa since 1965. One more Sub-division was sanctioned from December, 1971. Under this scheme 100 per cent Central assistance is given to the States to help them in indentifying and investigating the problem of water supply in difficult and scarcity areas, including collection of data etc.

The Government of Orissa have intimated that preliminary investigation, mapping and identification of about 7,000 villages have been completed in the scarcity and difficult areas of the State. The preliminary investigations are likely to be completed by the end of the IV Five Year Plan period.

These Divisions were neither meant for preparation of detailed plans and estimates nor for actual execution of water supply schemes. However, to supplement the scheme of Special Investigation Divisions, another scheme has been recently started under which Special Planning and Design Cells have been sanctioned to the States

with 100 per cent Central assistance. These Cells will prepare detailed plans and estimates for rural water supply schemes. Under this scheme, one Division was sanctioned to the Government of Orissa in December, 1971. However, due to various factors this Division could not be started in the year 1971-72. This is likely to start functioning during the current financial year.

United Nations Novel Programme at Baroda

5250. SHRI PRABHUDAS PATEL Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state

(a) whether Baroda in Gujarat has been selected as one of the seven cities in the World for a novel integrated programme of various United Nations Agencies to assist in Urban Community Development ,

(b) if so, whether UN team had recently visited Baroda , and

(c) what will be the main objects of and how many families will be benefited by the UN programme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF D P. CHATTOPADHYAYA) (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

डा० जगवान दास स्मारक ट्रस्ट,
नई दिल्ली

5251. श्री सम्मोह . क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या डा० जगवान दास स्मारक ट्रस्ट, 2-एक०, लाजपत नगर, नई दिल्ली

को उनके मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हो रहा है;

(ख) क्या जिस चार्टर्ड एकाउंटेंट ने उक्त ट्रस्ट के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा की थी, उसने यह प्रमाणित किया है कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सारी जानकारी ग्रथबा स्पष्टीकरण उसे उपबन्ध किए गए थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) . (क) डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, 2 एफ०, लाजपत नगर, नई दिल्ली को स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) ने अब तक निम्नलिखित अनुदान दिए हैं :-

(1) 1962-63 - 50,000 रु०; जनरल चार्टर्ड सफाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों को पूरा करने और उपस्कर खरीदने के लिए।

(2) 1963-64 - 12,000 रु०; बरामुबा, सीढिया, छज्जा और बहिरंग रोगी मंडप के निर्माण के लिए (6,000) और उपस्कर की खरीद के लिए (6,000 रु०)।

(3) 1964-65 - 1,000 रु०; मनोबौतिक चिकित्सा योग संस्थान, भगवानदास सेवा सदन, नई दिल्ली के लिए उपस्करों की खरीद करने हेतु।

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय में वर्ष 1964-65 के बाद से भगवान दास स्मारक ट्रस्ट को कोई अनुदान नहीं दिया है।

(ख) और (ग). जब सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने अपने हस्ताक्षर किए प्रमाण-पत्रों पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उन्हें लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी ग्रथबा स्पष्टीकरण नहीं दिए गए तो यही मानना पड़ता है कि उन्हें ऐसी सब जानकारी और स्पष्टीकरण उपलब्ध कर दी गई थी। प्रमाण प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पर्याप्त हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) से प्राप्त अनुदानों का डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली ने उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जिनके लिए वे मंजूर किए गए थे।

Misuse of Grants-in-Aid to All India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust

5252 SHRI AMBESH. Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1779 on the 3rd April, 1972 and state -

(a) whether misappropriation and embezzlement of the grant to All India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust has been mentioned in the audit report; and

(b) if so, the action taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. KISKU): (a) and (b). The information has been called for from Delhi Administration who is concerned with the matter.

गणेश फ्लोर मिल

5253. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणेश फ्लोर मिल, सब्जी मण्डी, दिल्ली बन्दे घरसे से बन्द पड़ी है, जिसके कारण काफी सख्या में श्रमिक बेकार हो गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने बन्द कारखानो को अपने हाथ में लेने की नीति अपनाई है ; और

(ग) उपरोक्त मिल को पुनः चालू करवाने प्रयत्न इसको अपने हाथ में लेने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषी मंत्रालय में राज्य मंत्री (अग्ना-साहिब पी० सिन्घे) : (क). मै० गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि०, दिल्ली, कानपुर और बम्बई के बहुत से उद्योगों के उत्पादक यूनिटों में कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें से कुछेक तो म्यूनाधिक सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं जबकि अन्य यूनिटों ने निम्नलिखित तारीखों से काम बन्द कर दिया है :-

1. दिल्ली की फ्लोर मिल धाम लगने से बन्द हो जाने के कारण —मार्च, 1956 से
2. दिल्ली में स्थित बिजली के पंचे का कारखाना—जून, 1970 से
3. दिल्ली का बनस्पति का कारखाना —सितम्बर, 1971 से ;

दिल्ली उच्चन्यायालय द्वारा जारी किए गए अदेशों के अनुसार जनवरी, 1972 से कम्पनी के निदेशक-बोर्ड को हटा दिया गया था और उसके स्थान पर न्यायालय द्वारा गठित नये बोर्ड को नियुक्त किया गया था।

(ख) जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानो के उत्पादन में पर्याप्त कमी हुई है प्रयत्न कमी होने की सम्भावना हो या जो 3 महीने की अवधि के लिए बन्द कर दिए गए हो, उनके बारे में औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सांख्यिक व्यवस्था की गई है ताकि सरकार उनका प्रबन्ध सीधे प्रयत्न उनकी प्रारम्भिक जांच करने के बाद जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, बशर्ते कि कुछेक शर्तें पूरी होती हो, अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत कर सके।

(ग) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

Medical Facilities given to Pensioners

5254. SHRI S. N. MISRA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether any medical facilities have been given to the pensioners; and

(b) if so, the nature thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) and (b). Central Services (Medical Attendance) Rule, 1944 and orders issued thereunder do not envisage provision of any medical facilities to Central Government pensioners.

However, medical facilities under the Central Government Health Scheme have been extended to the Central Government pensioners in the cities where this scheme has been enforced viz. Delhi, Bombay, Allahabad and Meerut on payment of prescribed contribution

Rationalisation of Price of Chemical Fertiliser

5225. SHRI RANABAHADUR SINGH:
SHRI MAHADEEPAK SINGH
SHAKYA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have any concrete proposal to rationalize the prices of chemical fertilisers by reducing the points of handling and distribution in view of a written request by a number of Members of Lok Sabha; and

(b) if so, the main feature thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHAB P SHINDE) (a) and (b). Government appreciate the anxiety of the Hon'ble Member that the numbers of tiers in the distribution system as well as the cost of distribution should be reduced to the minimum possible. A two-tier distribution system obtains with the Fertiliser Corporation of India, the major public sector manufacturer of fertilisers. Government, however, have no proposal to lay down rigidly the number of tiers in the distribution channel, but would ensure that the total cost of distribution would not exceed the authorised margins.

In the cooperative distribution system which accounts for nearly half of the total fertilisers sold in the country, there is generally a three-tier distribution system as in Japan. The State Apex Marketing Society, however, cannot but accept the

responsibility for financing the distribution of fertilisers but passes on the consignment generally to the Block Level Society for stocking in advance of the season. Even though three-tiers may be involved, the total cost of distribution is not to exceed the normal margin and each tier is to keep a portion of the margin proportionate to the services rendered by it. However, the system is constituted differently in each State. The National Cooperative Development Corporation have set up an Expert Committee for studying and streamlining the cooperative distribution system in different States so that the farmers can get fertilisers at the minimum possible cost

The statutory maximum prices of fertilisers exclusive of taxes and duties in the last three years have remained stable; and in case of Urea and Ammonium Sulphate, Government have reduced the prices by Rs. 20 and Rs 100/- respectively per tonne. The National Commission on Agriculture have reported that the cost of distributing fertilisers including the cost of storages, transport etc, have increased. Every effort, however, will be made to hold down the consumer prices of fertilisers to the existing level.

Restoration of Normalcy in Universities

5256. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of fact that many Universities of the country are in turmoil on account of acute mal-administration with the result that the grants sanctioned by the University Grants Commission for their development are not being properly utilised; and

(b) if so, what measures the University Grants Commission propose to take or recommend to the State Governments con-

cerned for the restoration of normal condition in Universities that are in a disturbed condition, as Patna University ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): (a) The University Grants Commission has no specific information to indicate that many universities of the country are in turmoil on account of acute mal-administration. As for proper use of the development Grants paid by the Commission, the grantee institutions are required to submit audit accounts and utilisation certificates duly certified by the statutory auditors to the effect that the grant has been utilised for the purpose for which it is sanctioned.

(b) The University Grants Commission has not received any reference from any State Government for the restoration of normal conditions in the university. In the event of such a reference being received, the Commission would examine the matter thoroughly and recommend suitable steps to the State Government in the light of the problems being faced by the university.

Fall in the Price of Arecanut

5257. SHRI C. JANARDHANAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the price of Arecanut has gone down to a very low level; and

(b) if so, the steps taken by Government to stop this downward trend in price and ensure a fair price for the farmers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) There has been a fall in the prices of arecanut in recent years; consequently, in several markets prices have fallen below last year's level.

(b) The Government has received some representations in this regard and the issue is being considered.

Export of Wheat, Rice and Sugar

5258. SHRI S. N. MISRA :

SHRI PAMPAN GOWDA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) that target for the export of wheat, rice and sugar;

(b) names of countries and the extent of exports in terms of money; and

(c) the method by which payments are received from the various countries to whom exports have been made in terms of money ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) The export target for sugar is 1 lakh tonnes and for superior basmati rice 25,000 tonnes for the year 1972-73. No target has been fixed for wheat.

(b) *Rice* is likely to be exported to Saudi Arabia, Trucial States, Kuwait, U. K., U. S. S. A., Canada, Africa, Singapore, Hongkong, Fiji and Mauritius; its value may be of the order of Rs. 4.5 crores. *Sugar* will be exported to U.K and U.S.A.; its value will be about Rs. 12 crores,

(c) Payments are generally received through letters of credit.

Survey of Ground Water In Famine Affected Areas

5259. SHRI BIRENDER SINGH RAO :

SHRI HARI KISHORE SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) Whether some State Governments approached the Central Government to undertake survey of underground water in the chronically famine-affected areas of their States;

(b) if so, the names of such States; and

(c) whether the said survey has since been conducted by the Central Government and if so, the areas surveyed and to be surveyed in the current year and the programme drawn in this connection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF AGRICULTURE
(PROF. SHER SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh Bihar, Madhya Pradesh and Maharashtra.

(c) The Central Ground Water Board (subordinate office under the Ministry of Agriculture) in conducting groundwater exploration in different parts of the country.

In Gujarat, Central Ground Water Board has done work in parts of districts Kutch, Banaskantha, Sabarkantha and Mehsana. Further work is being done in districts Mehsana and Banaskantha.

In Rajasthan, surveys have been conducted in parts of districts, Jodhpur, Jalore, Jaisalmer, Barmer, Pali, Sikar, Jhunjhunu, Nagaur, Alwar and Ganganagar. The Central Ground Water Board is now working in district Nagaur and more work would also be done in districts Churu, Sikar, Jhunjhunu and Bikaner.

In Uttar Pradesh works has been done in districts Pratapgarh, Gahzipur, Ballia, Mirzapur, Varanasi, Allahabad, Jaunpur, Banda and Hamirpur. Further work is being done in district Azamgarh and after that districts Ballia and Allahabad would taken be up.

In Bihar the Central Ground Water Board has done work in districts Muzafar-

nagar, Saran, Dharbanga, Gaya, Shahbad, Mongry and Champaran. In 1972-73, some more work is to be done in Mohania area of district Shahabad.

In Madhya Pradesh also some survey has been proposed under the Drought Prone Areas Programme. Under this programme, surveys are being conducted in districts Betul, Dhar Jhabua and Sidhi by the state Ground Water Directorate.

Maharashtra Government have also written to us for undertaking groundwater surveys in districts Ahmednagar, Nasik, Poona, Sangli, Satara and Sholapur. A groundwater survey project covering some of these areas would be shortly put on the ground by the Central Ground Water Board.

उठाऊ सिंचाई के लिये मध्य प्रदेश
में राशि का आवंटन

5260. श्री अरविंद नेतान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश के लिए कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) कितने विद्युत चालित पम्प लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राशि मन्त्री (श्री० शेर सिंह) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिसलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।